



भारत का गज़त पत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 393]

नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 4, 1982/भाद्र 13, 1904

No. 393]

NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 4, 1982/BHADRA 13, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दो आती है जिससे कि यह अलग संकलन के लिये इसे
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

उद्योग संवालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

ग्रामीण

नई दिल्ली, 4 सितम्बर, 1982

का०आ० 648/(अ)/18 काह/प्राई०डी०आर०ए०/82:—केन्द्रीय सरकार
में भारत सरकार के भूत्युवं प्रौद्योगिक विकास विभाग के प्रादेश में
का०आ० 104(अ)/18कक/प्राई०डी०आर०ए०/79 तारीख 10 मार्च,
1979 द्वारा यथा उपायित ग्रामीण स० का०आ० 529(अ)/18कक/
प्राई०डी०आर०ए०/74, तारीख 6 सितम्बर, 1974 द्वारा (जिसे इसमें
इसके पश्चात् उक्त ग्रामीण कहा गया है) सचिव, बंदू और राज्य उद्योग
विभाग, पश्चिमी बंगाल सरकार को (जिसे प्रश्न सचिव प्रौद्योगिक विभाग पश्चिमी
विभाग पश्चिम बंगाल सरकार कहा जाता है) (जिसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त ग्रामीण विभाग कहा गया है) ऐसत् इंडिया बोल्टिंग एंड कार्टन
मिल्स लिमिटेड, सौरमपुर, पश्चिमी बंगाल का (जिसे इसमें इसके पश्चात्
उक्त ग्रामीण विभाग कहा गया है) तारीख 6 सितम्बर, 1975 से
पांच वर्ष की अवधि के लिये प्रबन्ध ग्रहण करने के लिये प्राप्ति किया था;

ग्रामीण केन्द्रीय सरकार की यह राय थी कि सोकहित में यह समीक्षीन
है कि उक्त ग्रामीण विभाग को उपयुक्त पांच वर्ष के समान होने के
बावजूद भी प्रभावी बना रहा था विवेद ग्रामीण उद्योग उद्योग, 5 सितम्बर, 1982 तक
674 GI/82

की जिसके प्रत्यंगत वह तारीख थी है, प्रतिरेक अवधि के लिये इसे
जारी रखने के लिये वर्ष-वर्ष पर निरोग जारी किये थे [शेख भात
सरकार के ग्रामीणिक विकास विभाग सं. का०आ० 512(अ)/18कक/
प्राई०डी०आर०ए०/78, तारीख 4 सितम्बर, 1979, का०आ० 748
(अ)/18कक/प्राई०डी०आर०ए०/80, तारीख 5 सितम्बर, 1980 और
684(अ)/18कक/प्राई०डी०आर०ए०/1981 तथा का०आ० 125(अ)/
18कक/प्राई०डी०आर०ए०/82 तारीख 5 मार्च, 1982];

ग्रामीण सरकार की राय है कि सोकहित में यह समीक्षीन है कि
उक्त ग्रामीण विभाग का प्रबन्ध उक्त ग्रामीण विभाग द्वारा उक्त मास
की ग्रामीण विभाग के लिये आरं रखा जाये;

प्रत: केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास ग्रामीण विभाग) प्रधिनियम,
1951 (1951 का 85) की धारा 18 कक को उपधारा (2) द्वारा
प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निरेश देती है कि उक्त ग्रामीण,
5 मार्च, 1983 तक जिसमें यह तारीख भी सम्मिलित है यह उक्त मास
की ग्रामीण विभाग के लिये प्रभावी रहेगा।

[सं. 2/14/80-प्र०प०म००]

जन्म किशोर मोर्चा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

New Delhi, the 4th September, 1982

ORDER

S.O. 649(E)/18FA/18AA/IDRA/82.—Whereas by the Order of the Government of India in the late Ministry of Industrial Development No. S.O. 128(E)/18FA/18AA/IDRA/73, dated the 5th March, 1973, the Central Government had authorised a body of persons (hereinafter referred to as the authorised person) to take over the management of the whole of the industrial undertaking known as Messrs Krishna Silicate and Glass Works Limited, Calcutta, for a period of five years from the 5th March, 1973.

And whereas by the Orders of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 146(E)/18FA/18AA/IDRA/78, dated the 3rd March, 1978, No. S.O. 145(E)/18FA/18AA/IDRA/80, dated the 5th March, 1980, No. S.O. 144(E)/81, dated the 4th March, 1981, No. S.O. 685(E)/18FA/18AA/IDRA/81, dated the 4th September, 1981, and S.O. 123(E)/18FA/18AA/IDRA/82 dated the 4th March, 1982, the Central Government authorised the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for further periods upto and inclusive of 4th September, 1982.

And whereas the Central Government, being of the opinion that it was expedient in the interest of general public that the authorised person should continue to manage the said industrial undertaking, made an application under the proviso to sub-section (2) of section 18FA of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the Calcutta High Court praying for the continuance of such management for a further period of one year.

And whereas the said High Court, by its Order dated the 2nd September, 1982, permitted the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year.

And, now in exercise of the powers conferred by the proviso to sub-section (2) of section 18FA, read with section 18AA, of the said Act, the Central Government hereby directs the authorised person to continue to manage the said industrial undertaking for a further period of one year commencing from the 5th September, 1982.

[F. No. 2(1)/80-Cus.]

C. K. MODI, Jt. Secy.